

## **Haryana Human Rights Commission : मानवाधिकार आयोग के पास हजारों शिकायतें पेंडिंग, कुल शिकायतों में से 70% अकेले पुलिस विभाग के खिलाफ**

<https://haryana.indianews.in/haryana/thousands-of-complaints-pending-with-haryana-human-rights-commission-70-of-the-total-complaints-are-against-the-police-department-alone/>

[Amit Sood](#) • LAST UPDATED : December 2, 2024

**India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Human Rights Commission : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की तर्ज पर साल 2012 में अस्तित्व में आए हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबे समय से लंबित चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद शिकायतों के निपटान के काम के स्पीड पकड़ने की उम्मीद है। नियुक्तियां नहीं होने से 1 साल से ज्यादा समय तक आयोग का काम प्रभावित हुआ। इसी कड़ी में आया है कि करीब डेढ़ साल तक आयोग का काम न होने के चलते हजारों शिकायतों पेंडिंग हैं जिनका निपटान होना है।

### **Haryana Human Rights Commission : जुलाई 2023 में कोर्ट लगी थी, करीब डेढ़ साल की अवधि में हजारों शिकायत आईं**

मानवाधिकार आयोग से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार हर महीने औसतन मानवाधिकार आयोग के पास सुनवाई के लिए 400 से 500 नए मामले आते हैं। आयोग में आखिरी बार सुनवाई जुलाई, 2023 में हुई थी और बीच में नवंबर 2023 तक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते आयोग का काम ठप रहा, हालांकि कुछ पुरानी शिकायतों को लेकर काम होता रहा।

अनुमानित तौर पर आयोग के पास औसतन हर रोज 15 से 20 शिकायतें आती हैं लेकिन चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के चलते आयोग का काम प्रभावित होने की जानकारी भी लोगों को हो गई थी। इस लिहाज से आयोग के पास आने वाली शिकायतों में भी व्यापक तौर पर कमी आई। इसलिए इस लिहाज से अब तक कई हजार नए मामले आए। ये भी बता दें कि आयोग के पास तीन तरीके से शिकायतें आती हैं। पीड़ित मेल से शिकायत भेजता हो, इसके अलावा फिजिकली भी शिकायत भेजी जाती है। वहीं इसके अलावा आयोग कई बार मामले की गंभीरता को देखते हुए सू मोटो (स्वत संज्ञान) भी लेता है।

### **चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी लगातार चर्चा में रही**

मानवाधिकार आयोग में लंबे समय से खाली पड़े चेयरमैन के पद और दो सदस्यों की नियुक्ति के मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय सीमा में 3 सप्ताह में नियुक्ति करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसको लेकर बाद में फिर सरकार ने कोर्ट में लिखकर दिया था कि आचार संहिता हटने के 21 दिन में कमीशन काम करने लगेगा।

अप्रैल में मामले को लेकर सुनवाई हुई थी जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया कि आचार संहिता हटने के तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सभी पद सकारात्मक रूप से भरे जाएं। चूंकि अब आचार संहिता हट चुकी है और यह तय माना जा रहा है कि नियुक्ति कर दी जाएगी। यह बता दें कि इससे पहले 31 मार्च तक चेयरपर्सन और दो सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, हरियाणा सरकार में बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ लेकिन किसी कारणवश पद नहीं भरे जा सके। जिस तरह से मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते मामलों पर सुनवाई नहीं हुई और शिकायतें पेंडिंग रही। यह मामला लगातार चर्चा में रहा। लगातार सवाल उठे कि नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई। जानकारी में यह भी सामने आया कि अफसरशाही के चलते कहीं ना कहीं नियुक्तियों में देरी हुई।

### **इस विभाग ने सोचने को किया मजबूर**

आयोग से प्राप्त जानकारी अनुसार आयोग के पास जितनी भी शिकायत आती हैं अनुमानित तौर पर उनमें से औसतन 70 फीसद से ज्यादा शिकायत तो पुलिस कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ ही होती हैं जो कि चिंतनीय है। आयोग पहले भी पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता रहा है। इनमें पुलिस विभाग के खिलाफ यौन शोषण, शोषण, वसूली, हिरासत में मारपीट, रिश्वत और छेड़छाड़ जैसी गंभीर शिकायतें भी रहती हैं।

इसके अलावा कस्टडी में मारपीट या फिर कस्टडी में मौत को लेकर भी शिकायत आयोग के पास आती है। वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत आयोग के पास रिसीव होती हैं। आयोग में आने वाले मामलों में ज्यादातर मामलों में पुलिस के अलावा प्रशासन, परिवार पहचान पत्र, सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलने, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, प्रॉपर्टी पर कब्जा, अतिक्रमण, समाज कल्याण विभाग तथा डॉक्टरों द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस आदि से संबंधित होते हैं। बहुत से मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान लेता है और लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई करता है।

### **19 माह बाद चेयरमैन और 14 महीने बाद सदस्यों की नियुक्ति**

हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद क्रमशः पिछले 19 और 14 महीने से खाली पड़े हुए थे। कैथल के एक व्यक्ति की ओर से याचिका दायर किए जाने पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को फटकार लगाते हुए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश जारी किए थे। इस बीच हरियाणा में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव आ गए, जिसके चलते आचार संहिता लगने से नियुक्तियां सिरें नहीं चढ़ सकीं।

### **ये बोलीं हरियाणा मानवाधिकार आयोग की सदस्य दीप भाटिया**

हरियाणा मानवाधिकार आयोग की सदस्य दीप भाटिया ने कहा कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद शिकायतों के निपटान के काम अब तेजी आएगी। नियुक्तियां न होने से लगातार नई शिकायतें पर काम नहीं हो पाया। आयोग के पास आने वाली कुल शिकायतों में से 70 फीसदी से ज्यादा अकेले पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ आती हैं। हालांकि सभी राज्यों में ऐसी

ही हालत है क्योंकि पुलिस विभाग की डीलिंग ज्यादा है। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति न होने के चलते भी काम बाधित होने पर शिकायतों की संख्या में कमी आई।

## HC: Preserve bodies of Maoists killed in Telangana

<https://www.hindustantimes.com/india-news/hcpreserve-bodies-of-maoists-killed-in-telangana-101733166286743.html>

By [Srinivasa Rao Apparasu](#), Hyderabad

Dec 03, 2024 07:52 AM IST

The petitioner said there were suspicions that police had trapped Maoists by arranging food laced with poison and later tortured them

The Telangana high court has directed the Mulug district police to preserve bodies of the seven Maoists killed in a gunfight with security forces on Sunday, after a non-profit organization moved the court alleging that the encounter was fake.

Hearing a lunch-motion petition, moved by not for profit organization Civil Liberties Committee, the court also ordered the police to allow families of the slain Maoists to view their bodies.

The petition, CLC general secretary, alleged that the police trapped the Maoists by lacing food with poison and tortured them. "After the Maoist lost consciousness, they were shot dead in the name of encounter," Rao said.

He also said that the police hurriedly shifted the bodies to a hospital for post-mortem without the consent of their families in violation of the **National Human Rights Commission** guidelines.

The petition sought that autopsy of the Maoists be conducted again under the supervision of expert doctors. "The corpses should be preserved so that they do not decompose and handed over to the family members," the petition said.

The counsel for the police contended that the bodies were immediately shifted to Mulug hospital for security reasons. "The post-mortem examinations were conducted under the supervision of 13 doctors and forensic experts from Kakatiya Medical College and the process was video-recorded," he said.

### **The court adjourned the hearing to Tuesday.**

Seven members of the banned CPI (Maoist), including a senior leader carrying a ₹20 lakh reward, were killed in Sunday's gunfight. This was only the second major operation in Telangana in 10 years, following the killing of 10 Maoists in Jayashankar Bhupalpally district in March 2018. In September, six Maoists, including squad commander Lachanna who carried a ₹10 lakh reward, were killed in Bhadradri Kothagudem district.

Meanwhile, a tense atmosphere prevailed in the Eturnagaram area, as the Mulug district police conducted combing operations.

“The Maoists put up banners in the region a couple of days ago calling upon the people to observe People’s Liberation Guerilla Army martyrs’ week. They are targeting innocent tribals suspecting them to be police informers. Hence, we are not leaving any chance in ensuring security,” a senior police official said.

## Keonjhar में डेंगू से हुई मौतों पर एनएचआरसी ने सरकार को नोटिस जारी किया

<https://jantaserishta.com/local/odisha/nhrc-issues-notice-to-government-on-dengue-deaths-in-keonjhar-3676513>

2 Dec 2024 10:42 AM

**Kendrapara केंद्रपाड़ा:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एचएंडएफडब्ल्यू) विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर क्योँझर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया है। भारत के शीर्ष मानवाधिकार पैनल ने पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया, जिसमें क्योँझर में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद, जहां कथित तौर पर जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) और मेडिकल कॉलेज में अपर्याप्त देखभाल और उपचार के कारण निवासी डेंगू से मर रहे हैं। क्योँझर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का गृह जिला है। याचिका में 2 अक्टूबर की एक समाचार रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया,

जिसमें 37 वर्षीय बीरी विश्वकर्मा की 1 अक्टूबर को डेंगू के कारण मृत्यु के साथ-साथ कई अन्य प्रभावित निवासियों की मृत्यु का विवरण दिया गया था। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि मेडिकल कॉलेज और सुपर-स्पेशियलिटी जिला अस्पताल की मौजूदगी के बावजूद, गरीब आदिवासी मरीज अक्सर उचित उपचार के बिना मर जाते हैं या उन्हें अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए रेफर कर दिया जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा खनन रॉयल्टी देने वाले जिलों में से एक क्योँझर, जो जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में काफ़ी योगदान देता है, अभी भी अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निधि से ग्रस्त है। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि डेंगू वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए रक्त के नमूने कटक या भुवनेश्वर भेजे जाने चाहिए, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण मौतों में वृद्धि हुई है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप करने और निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है। NHRC ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आगे की कार्रवाई और जानकारी के लिए आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजी गई है।

## **NHRC directs Tamil Nadu chief secretary to ensure basic amenities are provided to ex-Manjulai workers**

<https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2024/Dec/03/nhrc-directs-tamil-nadu-chief-secretary-to-ensure-basic-amenities-are-provided-to-ex-manjulai-workers>

*Further, with regard to the matter of cancellation of VRS orders, issued by the BBTCL, and rehabilitation of the individual workers, the same are under consideration before the forest bench of the high court.*

**Express News Service** Updated on: 03 Dec 2024, 8:51 am 1 min read

TIRUNELVELI: The National Human Rights Commission (NHRC) directed the Tamil Nadu chief secretary to ensure that all basic amenities including water, electricity, medical facilities, education, transportation and rations distribution, are provided to the former Manjulai tea estate workers and instructed him to file an action taken report within six weeks. The commission gave the directions while hearing a case filed by Puthiya Tamilagam founder Dr K Krishnasamy on Monday.

The NHRC observed that their investigation team had found that the allegations levelled by the workers about disruption in provision of essential facilities such as food grains, dispensary, electricity, and public transport were true. "The commission has considered the findings of its investigation division and notices that the Madurai Bench of the Madras High Court has maintained a "status quo," thereby halting evictions until the case was resolved.

Further, with regard to the matter of cancellation of VRS orders, issued by the BBTCL, and rehabilitation of the individual workers, the same are under consideration before the forest bench of the high court. However, the enquiry has ascertained facts of disruption/reduction of essential services, which in fact are basic human necessities essential to lead a dignified life," the commission said.

"The commission directs the Tamil Nadu chief secretary to look into the matter and ensure that all basic amenities including water, electricity, medical facilities, education, transportation, rations distribution, and other welfare schemes of the state and central governments be provided to all the workers/residents and their family members residing in the Singampatti/Manjulai Tea Estates Forest area. Action taken report in the matter should be presented before the commission within six weeks of this direction," it said.

## **NHRC India Concludes Online Internship Program with 52 Students to Champion Human Rights**

<https://www.devdiscourse.com/article/education/3178788-avadh-ojha-joins-aap-education-focus-at-the-forefront>

“Your journey as human rights defenders begins here. Use your learnings to foster empathy, compassion, and unwavering commitment to the ideals of liberty and justice,” said Sayani.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 02-12-2024 21:39 IST | Created: 02-12-2024 21:39 IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India, successfully concluded its two-week online short-term internship program on November 30, 2024, with 52 students from diverse universities across the country participating. The program began on November 18, 2024, and included students from both urban and remote regions, reflecting NHRC's commitment to inclusivity and broader engagement.

During the valedictory session, Smt. Vijaya Bharathi Sayani, NHRC Acting Chairperson, congratulated the participants for completing the internship and emphasized the importance of their role as future advocates for human rights. She encouraged the interns to integrate the insights gained during the program into their efforts to create a society rooted in justice, equality, and fraternity.

“Your journey as human rights defenders begins here. Use your learnings to foster empathy, compassion, and unwavering commitment to the ideals of liberty and justice,” said Sayani.

### **Secretary General's Address**

Shri Bharat Lal, NHRC Secretary General, underscored the importance of translating knowledge into action for the protection of human rights. He urged the interns to embody the core principles of equality and fraternity in their endeavors, fostering positive societal change.

“The practical exposure and understanding of human rights protection mechanisms should reflect in your actions, reinforcing the spirit of inclusivity and equality,” he added.

### **Comprehensive Learning Experience**

Shri Devendra Kumar Nim, NHRC Joint Secretary, presented the internship report, highlighting the program's comprehensive approach. Key activities included:



**Interactive Sessions:** Senior NHRC officials, human rights experts, and civil society representatives conducted detailed discussions on various aspects of human rights.

**Virtual Tours:** Interns visited key institutions such as Mandoli Jail, a Delhi Police Station, and Asha Kiran Shelter Home, providing firsthand insights into human rights challenges and ground-level realities.

**Competitions and Projects:** The program included activities such as book reviews, group research project presentations, and a declamation competition, with winners announced during the session.

The exposure allowed interns to better understand government mechanisms and the challenges faced by vulnerable populations, equipping them to advocate for human rights effectively.

### **Recognizing Excellence**

Winners of the competitions were acknowledged for their exceptional contributions, showcasing innovative ideas and commitment to human rights advocacy.

### **Closing Remarks**

The program concluded with a vote of thanks from Lt. Col. Virender Singh, Director of the NHRC, who expressed appreciation for the interns' dedication and enthusiasm.

### **Building a Legacy**

The internship program reflects NHRC's ongoing efforts to nurture a new generation of human rights defenders capable of addressing complex societal challenges. By integrating theoretical knowledge with practical experiences, the Commission aims to foster leaders who champion dignity, justice, and equality for all.

The NHRC looks forward to seeing these young advocates make meaningful contributions to building a more inclusive and equitable society.

## **NHRC led India's two-week online short-term internship concludes Admin 03 December 2024**

<https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/8790/nhrc-led-india-s-two-week-online-short-term-internship-concludes/>

The two-week online short-term internship programme organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India has concluded.

It commenced on 18th November, 2024. 52 students from various universities in different regions and far-flung areas of the country completed it.

Addressing the valedictory session on Monday, NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani congratulated the students for successfully completing their internship with the Commission. She expressed the hope that the interns would carry forward the insights gained during the programme to promote and protect the human rights of every individual.

She encouraged them to evolve as human rights defenders to contribute meaningfully to building a more inclusive and equitable society. She emphasised the importance of embodying empathy, compassion, and a steadfast commitment to justice, liberty, equality, and fraternity.

In his address, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal said that the interns should reflect the learning gained in their actions for the cause of human rights. He encouraged the interns to internalise core human values, uphold the ideals of fraternity and equality, and actively work towards fostering positive change in society.

Shri Devendra Kumar Nim, Joint Secretary, NHRC, presented the internship report. Besides the sessions on varied aspects of human rights by the senior NHRC officers, experts and civil society representatives, the interns were also taken for virtual tours to the Mandoli Jail, Police Station and Asha Kiran Shelter Home in Delhi. They were given an understanding of the functioning of various government institutions, human rights protection mechanisms, ground realities and requirements for protecting the human rights of the vulnerable segments of society.

Shri Nim also announced the winners of the book review, group research project presentation, and declamation competition. The Director, Lt Col Virender Singh delivered the vote of thanks.

## **NHRC notice to govt over Keonjhar dengue deaths**

<https://www.orissapost.com/nhrc-notice-to-govt-over-keonjhar-dengue-deaths/>

PNN/Agencies Updated: December 2nd, 2024, 09:07 IST in State, Top Stories

Kendrapara: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Principal Secretary of the state Health & Family Welfare (H&FW) department, seeking a detailed report on the lack of healthcare facilities in Keonjhar district. The notice was prompted by a petition filed by rights activist Radhakanta Tripathy.

The apex human rights panel of India passed the order last week, following concerns raised by the petitioner about the dire condition of healthcare in Keonjhar, where residents are reportedly dying of dengue due to inadequate care and treatment at the District Headquarters Hospital (DHH) and medical college.

Keonjhar is the home district of Chief Minister Mohan Charan Majhi. The petition highlighted a news report from October 2, which detailed the death of 37-year-old Biri Biswakarma October 1 due to dengue, alongside several other affected residents. Tripathy argued that despite the presence of a medical college and a super-speciality district hospital, poor tribal patients often die without proper treatment or are referred to facilities in other regions. Keonjhar, one of India's highest mining royalty-paying districts with substantial contributions to the District Mineral Foundation (DMF), still suffers from inadequate public healthcare funding. Tripathy contended that blood samples have to be sent to Cuttack or Bhubaneswar to confirm the presence of the dengue virus, a time-consuming process that has led to an increase in deaths.

The complainant urged the commission to intervene and take remedial action to safeguard the health and lives of residents. The petition also referenced a Supreme Court ruling that recognises the right to health as part of the fundamental right to life under Article 21 of the Indian Constitution. The NHRC has directed the authorities to take necessary action and submit a report within four weeks. A copy of the order has been sent to the Chief Secretary for further action and information.

## **NHRC, India's two-week online short-term internship concludes**

<https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2079718>

Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani urges the interns to carry forward the insights gained during the programme to promote and protect the human rights of every individual

52 students from various universities in the country attended

Posted On: 02 DEC 2024 3:40PM by PIB Delhi

The two-week online short-term internship programme organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India has concluded. It commenced on 18th November, 2024. 52 students from various universities in different regions and far-flung areas of the country completed it.

Addressing the valedictory session, NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani congratulated the students for successfully completing their internship with the Commission. She expressed the hope that the interns would carry forward the insights gained during the programme to promote and protect the human rights of every individual.

She encouraged them to evolve as human rights defenders to contribute meaningfully to building a more inclusive and equitable society. She emphasised the importance of embodying empathy, compassion, and a steadfast commitment to justice, liberty, equality, and fraternity.

In his address, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal said that the interns should reflect the learning gained in their actions for the cause of human rights. He encouraged the interns to internalise core human values, uphold the ideals of fraternity and equality, and actively work towards fostering positive change in society.

Shri Devendra Kumar Nim, Joint Secretary, NHRC, presented the internship report. Besides the sessions on varied aspects of human rights by the senior NHRC officers, experts and civil society representatives, the interns were also taken for virtual tours to the Mandoli Jail, Police Station and Asha Kiran Shelter Home in Delhi. They were given an understanding of the functioning of various government institutions, human rights protection mechanisms, ground realities and requirements for protecting the human rights of the vulnerable segments of society.

Shri Nim also announced the winners of the book review, group research project presentation, and declamation competition. The Director, Lt Col Virender Singh delivered the vote of thanks.

## Odisha govt to launch major programme against cervical cancer

<https://www.thestatesman.com/india/odisha-govt-to-launch-major-programme-against-cervical-cancer-1503371422.html>

The Odisha government will launch a major programme for immunisation of young girls against cervical cancer soon, Odisha's minister for health and family welfare, Mukesh Mahaling said.

Statesman News Service | Bhubaneswar | December 2, 2024 7:08 pm

The Odisha government will launch a major programme for immunisation of young girls against cervical cancer soon, Odisha's minister for health and family welfare, Mukesh Mahaling said.

This programme will focus on young girls studying in schools and colleges to ward off the threat of the disease, Dr. Mahaling said while speaking at the inaugural function of the first National Conference on International Radiology (SUMUMIRCON) held at the SUM Ultimate Medicare (SUMUM) here.

The hospital had organised the conference in association with the Odisha Radiological and Imaging Association and Indian Society of Vascular and Interventional Radiology.

The minister described the conference as timely while saying that imaging and interventional radiology, two fields of radiology, had gained importance in recent times. He congratulated SUMUM for organizing the conference while saying that the hospital, along with Institute of Medical Sciences and SUM Hospital, faculty of medicine of SOA, had been writing new chapters in Odisha's healthcare history in recent times.

Dr. Mahaling also said the state government was working on a new scheme combining the Ayushman Bharat Yojana and Gopabandhu Jana Arogya Yojana schemes which would be rolled out from the next financial year. This scheme would help the people undergo free treatment in 27,000 hospitals in the country, he said.

Besides, the state government would recruit 250 Radiographers to be stationed in government hospitals across Odisha, he said.

Speaking on the occasion, Dr. Swetapadma Dash, Chief Executive Officer of SUMUM, said that SUMUM was the only hospital in the state which has a separate department for interventional radiology. This was enabling patients to undergo minimal invasive surgery, she said.

SOA Founder President Prof. (Dr.) Manojranjan Nayak also complimented SUMUM for organizing the conference which was of great importance.

The inaugural program was also addressed by Brig. (Dr.) Biraj Mohan Mishra, the hospital's Chief of Medical Services.

## **Preserve bodies of Maoists slain in encounter at Eturunagaram: HC to police**

<https://www.thehindu.com/news/national/telegana/preserve-bodies-of-maoists-slain-in-encounter-at-eturunagaram-hc-to-police/article68939371.ece>

Published - December 02, 2024 09:04 pm IST - HYDERABAD

Marri Ramu READ LATER PRINT

Justice B. Vijaysen Reddy of Telangana High Court on Monday directed the Station House Officer of Eturunagaram in Mulugu district to preserve the bodies of seven persons, members of the the outlawed CPI-Maost who were killed in an exchange of fire with the police the previous day, at the area hospital of Eturunagaram till Tuesday.

Hearing a writ petition filed by K. Ilamma, wife of one of the slain Maoists Mallaiah, by way of lunch motion, the judge directed the police to permit the petitioner to see her husband's body. The petitioner informed the bench that she learnt about the 'police encounter' at Chalpakka forest in Eturunagaram through TV and web-based news channels. She told the court that she realised that her husband was also killed in the encounter on seeing his pic among those of the seven slain persons.

The petitioner's counsel Suresh Kumar, presenting his contentions, said the petitioner learnt from Civil Liberties Committee general secretary N. Narayana Rao that police ensured food laced with poison was served to the seven persons who were gunned down by police after they fell unconscious. Photos of the persons killed in the encounter suggested that they were tortured before being shot dead, the counsel said.

The petitioner wanted the HC to instruct the police to register murder case under Section 103 of BNS into the alleged police encounter and constitute a Special Investigation Team for fair probe. Ms. Ilamma also requested the court to order a Special Team of Forensic Doctors from MGM Medical College of Warangal to conduct post-mortem examination as per the directions of National Human Rights Commission while preserving viscera and clothes of the killed persons.

She requested the court to conduct inquest for the PME in her presence and call for records of general diary of the police station, First Information Report and autopsy report for adjudication of the matter. Lawyer Suresh Kumar sought to know why the police had hurriedly conducted autopsy of the bodies without shifting them to MGM hospital (where expert and senior doctors were available) to conduct autopsy if the encounter was genuine. He wanted the government to explain why the police did not permit the petitioner to see her husband's body.

Government Pleader for Home Mahesh Rajesh, refuting the contentions of the petitioners counsel, said the PME of the bodies was already conducted with forensic experts of Eturnagaram hospital. The bodies were not shifted to MGM hospital apprehending law and order issues.

The matter was posted to Tuesday with a direction to GP for Home to secure written instructions in the matter along with the details of forensic doctors who conducted the autopsy.



## Telangana HC Orders Preservation of Maoists Bodies for Inquiry Telangana

<https://www.deccanchronicle.com/southern-states/teLANGANA/teLANGANA-hc-orders-preservation-of-maoists-bodies-for-inquiry-1843428>

Vujjini Vamshidhar2 December 2024 10:22 PM

Hyderabad: The Telangana High Court on Monday directed the Eturunagaram police to preserve the bodies of the seven Maoists who were killed in a gunfight in the Chalpaka forests of Mulugu district on Sunday. The court also allowed the petitioner, wife of one of the deceased, to see her husband's body and those of the others. LOOK AT ME BEING ALL FESTIVE AND SHAT The court would decide on Tuesday the request of the relatives of the deceased Maoists that the postmortem be conducted as per the procedure prescribed by the National Human Rights Commission (NHRC)

Justice B. Vijaysen Reddy heard by way of a lunch motion, a writ petition filed by Kalavalla Illamma, alias Meena, wife of Mallaiah, one of the deceased, to permit her to be part of the inquest of all the seven bodies. The bodies are to be preserved till Tuesday at the area hospital, Eturunagaram.

Suresh Kumar, counsel for the petitioner, informed the court that the Mulugu district police had ignored the petitioner's request to see the bodie which was in violation of Section 196 of the BNS.

The police worked in haste and went about the postmortem, without ensuring that the team of doctors, who perform the PME, also includes forensic experts. Counsel alleged that the police had poisoned the food consumed by the Maoists. After they consumed the food and unconscious, the police encircled the hideout, took the Maoists into custody, tortured and killed them.

Mahesh Raje, government counsel for home, informed the court that the postmortem examination was performed at the primary healthcare centre (PHC) in Eturunagaram, on Sunday with a team of doctors, which included forensic experts and the petitioner was permitted to see the body of her husband. Counsel for home informed the court that all the seven bodies were not shifted to MGM Hospital in Warangal as law and order issues could erupt. Justice Vijaysen Reddy posted the writ petition to Tuesday and directed counsel for home department to get written instructions furnishing details of the doctors, including the forensic science experts who had performed the PME.

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: हर व्यक्ति दे मानवाधिकारों को बढ़ावा: विजया भारती

<https://www.indiavoice.com/national-human-rights-commission-every-person-should-promote-human-rights/>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरनेट कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 52 छात्रों ने इसमें भाग लिया। एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी ने छात्रों को आयोग के साथ सफलतापूर्वक अपनी इंटरनेट पूरी करने के लिए बधाई दी।

By HO BUREAU | Updated Date December 2, 2024

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरनेट कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 52 छात्रों ने इसमें भाग लिया। एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी ने छात्रों को आयोग के साथ सफलतापूर्वक अपनी इंटरनेट पूरी करने के लिए बधाई दी।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षु प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने उन्हें अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए मानवाधिकार रक्षकों के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सहानुभूति, करुणा और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने कहा कि प्रशिक्षुओं को मानवाधिकारों के लिए अपने कार्यों में प्राप्त सीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने, भाईचारे और समानता के आदर्शों को बनाए रखने और समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। एनएचआरसी के संयुक्त सचिव देवेन्द्र कुमार निम ने इंटरनेट रिपोर्ट प्रस्तुत की। मनोरंजन » BIG BOSS में दीपक चौरसिया के अंदर दिखी चित्रा और जगजीत सिंह की झलक, गजल... एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली में मंडोली जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण शेल्टर होम के आभासी दौरे पर भी ले जाया गया।

उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थानों के कामकाज, मानवाधिकार संरक्षण तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकताओं की समझ दी गई।